स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–7, आषाढ–श्रावण 2068, जुलाई 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा।

अनुक्रम

आवरण लेख : अमरीका फिर मंदी में
बलि पर भारत को चढ़ाने की साज़िश
– विक्रम उपाध्याय /4

प्रतिक्रिया
सावधान! जनता जाग चुकी है
– के.एन. गोविन्दाचार्य /7

दृष्टिकोण
आर्थिक संवृद्धि का अमानवीय चेहरा
– डॉ. अश्विनी महाजन /9

अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था पर तिहरा दबाव
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /12

मुद्दा
खाओ अंगारे पीओ धुआं
– अवधेश कुमार /15

चिंतन
अमरीका का असली चेहरा
– डॉ. बनवारी लाल शर्मा /18

अंतर्राष्ट्रीय
अफगानिस्तान में भारत की भूमिका
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /21

सामयिकी
परमाणु करार के दुष्परिणाम
– ब्रह्मा चेलानी /23

पुस्तक समीक्षा
अमिताव घोष की पुस्तक : रिवर ऑफ स्मोक पर कुछ विचार
– कश्मीरी लाल /25

पड़ताल
लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से
विरोध प्रदर्शन करना सहन नहीं
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /28

समस्या
पूर्वोत्तर में गहराता खतरा – बलवीर पुंज /32

पर्यावरण : जीवन धारा बचाने का अभियान
– जवाहरलाल कौल /32

पाठकनामा/2, आंदोलन/36

पाठकनामा

नयी आशा और विश्वास की ज्योति स्वदेशी पत्रिका

मुझे स्वदेशी पत्रिका के नियमित अध्ययन, चिंतन, मनन करने से अनूठे आनंद की अनुभूति होती है। देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर व्यक्ति अवसाद से गुजर रहा है।ऐसे अंधकारमय समय में सभ्यता और संस्कृति समेत संस्कार और आचार व्यवहार में ह्रास होता जा रहा हैं। कुछ शेष बचने की उम्मीद छूटती जा रही है। ऐसे समय में 'स्वदेशी पत्रिका' के विभिन्न स्तंभों में प्रकाशित विचारोत्तेजक सामग्री जड़ीभूत जनजीवन में नयी आशा और विश्वास की ज्योति जगाती है।

स्वार्थों से प्रदूषित समाज का सुधार तभी होगा जब देश–विदेश के कोन–कोने के लोग 'स्वदेशी पत्रिका' का नियमित अध्ययन, मनन–चिंतन करें और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर व्यवहार में लाएं।

– देवेन्द्रनाथ मोदी, सुभाष नगर, जोधपुर–342002

भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी भारतीय एक हो

भ्रष्टाचार आज कैंसर की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। मंत्री, पुलिस अधिकारी, नौकरशाह और अन्य सरकारी कर्मचारी दिन–प्रति–दिन भ्रष्टाचार को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। उन्हें भारत की छवि से कोई लेना देना नहीं है – बस पैसा चाहिए – पैसा। आज आपको मकान बनाना हो, ड्राईविंग लाईसेंस बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, उच्च शैक्षिक संथान में दाखिला लेना हो या कोई टेंडर लेना हो या कोई भी कार्य करना हो। सब जगह रिश्वत ही रिश्वत का चलन है। सरकारी कर्मचारी कालेधन को कमाने में लगा हुआ है और जनता उसमें पिसती चली जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने अनशन किया, वही केन्द्र सरकार ने अन्ना के लोकपाल बिल पर अपना टालू रवैया अपनाया। जब चार जून को भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में बैठे बाबा रामदेव के शिविर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई मानवता को कलंकित करने वाली थी। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का? नहीं यह मुद्दा हम सभी भारतीयों का है। इसलिए हम भारतीय वासियों को एकजुट होकर भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिपाही के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा ताकि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत सौंपे न की 'भ्रष्टाचार में डूबा भारत'।

– महेन्द्र कुमार, C-130A, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली–59

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

अमेरिका में आज भी लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। वे चिंतित हैं कि कार खराब हो गई या नौकरी चली गई तो क्या होगा? वे यकीन से नहीं कह सकते कि बच्चों की कॉलेज की फीस दे पाएंगे या नहीं!

– बराक ओबामा

केंद्र सरकार हिंदुओं के मौलिक अधिकार छीनने के लिए सांप्रदायिक हिंसा निषेध विधेयक लाने जा रही है। इसके पारित होने के बाद देश में हिंदुओं का सकुशल रह पाना मुश्किल हो जाएगा।

– अशोक सिंघल

आजकल की फ़िल्मों में कहानी और गाने उस स्तर के नहीं हैं जैसे 70 के दशक में हुआ करते थे साथ ही समाज को प्रेरणा मिलती थी।

– अमिताभ बच्चन

संपादकीय

राहुल का किसान प्रेमः कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना

किसानों को आजादी के बाद से ही क्या मिला सिर्फ आश्वासन? इनकी पीठ पर चढ़कर सत्ता को छूने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इन्हें सिर्फ मुद्दा माना और उसे भुनाने के लिए हमेशा इनकी कुर्बानी देते रहे। कांग्रेस से ज्यादा किस पार्टी को किसानों की दुदर्शा के लिए जिम्मेदार मानें? पैसठ साल के अपने इस लोकतंत्र में ज्यादातर समय तो कांग्रेस ही केंद्र या राज्यों की सत्ता में रही है। फिर भी कांग्रेस यह कहने की हिम्मत कर रही है कि वह किसानों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन करेगी। वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। क्यों? संभवतः इसलिए कि एक बार फिर किसानों को बरगलाने का अवसर उत्तर प्रदेश में ही मिलने वाला है। यहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस यहां हाशिए पर बनी है। सत्ता में आने की बात तो दूर सत्ता के लिए दावेदारों में भी पिछले दो दशकों से गिनती नहीं हो पा रही है। इस बार मैदान थोड़ा खाली है। बसपा के जुल्मों से, सपा की वादा खिलाफी से भाजपा की निष्क्रियता से और बाकी छोटे मोटे दलों के अप्रासंगिक होने के कारण कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनकी दाल गल जाएगी? यह अलग बात है कि उनकी दाल ही काली है। किसान महापंचायत में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चार दिन में उन्होंने किसानों के बारे में जो सीखा वह दिल्ली में बैठ कर नहीं सीख सके। उन्होंने सीखा कि किस तरह किसानों की जमीन की उचित कीमत सरकार नहीं देती, उन्हें धोखा देती है। उन्होंने सीखा कि किस तरह एक निर्दयी सरकार किसानों पर जुल्म करती है। उन्होंने सीखा कि किसानों को सत्ता के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि किस तरह किसानों की पीठ पर बैठकर चुनावी बैतरनी भी पार किया जा सकता है। राहुल गांधी के लिए किसानों का मतलब संभवतः इतना ही है। अगर किसानों की परिभाषा वह इससे विस्तृत कर पाते तो उन्हें पता होता कि देश भर के एक फीसदी से भी कम किसान मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। 99 फीसदी किसान भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के कुछ बड़े शहरों की बात छोड़ दे तो किसानों को उनकी भूमि ही गले की फांस बन गई है। खेती छोड़ नहीं सकते और खेती उन्हें कुछ दे नहीं पाती। न तो समय पर उन्हें बीज मिलता है औरा न ,खाद मिलती है। हार मांस को गला कर अनाज पैदा भी किया तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। गम या खुशी दोनों अवसरों पर किसान अपनी जगीन बेच कर ही खर्च जुटा पाता है और कभी कर्ज लेकर कुछ करने की हिम्मत करता है तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। राहुल गांधी यह सब नहीं जानते नहीं तो किसानों की बात सिर्फ नोएडा और अलीगढ़ में जाकर नहीं करते। उत्तरप्रदेश में ही यदि किसानों की दशा जाननी हो तो उन्हें कुछ दिनों के लिए पूर्वांचल का भी दौरा करना चाहिए। यदि किसानों की दशा से वे इतने ही विचलित है तो उन्हें कुछ दिन के लिए बुंदेलखंड में डेरा डालना चाहिए। ताकि वह सीख सके कि जब सूखे से धरती फटती है तो किसान किस तरह खून के आसूं रोता है। खैर उन्हें उत्तरप्रदेश के किसानों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं हो, क्योंकि यहां कांग्रेस काफी दिनों से पराई सी नजर आ रही है। पर महाराष्ट्र तो कांग्रेस के लिए सहोदर है। वहां तो लगभग दस साल से सरकार चल रही है। वहां के किसानों के बारे में आकलन राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया। वे किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए नये कानून की चिंता में है। पर उन किसानों की चिंता क्यों नही कर पा रहे हैं जो कर्ज के कारण रोज जान दे रहे हैं। विदर्भ का विषय तो उनकी जानकारी में है। कितने परिवारों के आसूं उन्होंने पोछे। चलो मायावती की नीयत खराब है, महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार की नीयत तो सही रही होगी। फिर भी किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। आंध्र की हालत भी राहुल जानते होंगे। किसान वहां तबाह हो रहे हैं और न तो राज्य सरकार और न केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। उनकी खरीफ की फसल बारिश में इस इंतजार में बर्बाद हो गई कि सरकार आएगी उनकी फसलों की उचित कीमत देगी। पर वहां राहुल गांधी नहीं थे। इसलिए किसाानों के साथ अन्याय हो गया। कास राहुल गांधी कुछ और किसानों पर अध्ययन करते। पर क्या करे पूरे देश के किसान परेशान है। कितना अध्ययन करेंगे। पूरी उम्र निकल जाएगी। फिर मकसद चुनाव है अध्ययन नहीं। लोग भी समझते है और किसान भी।

अमरीका फिर मंदी में

बलि पर भारत को चढ़ाने की साज़िश

हाल के दिनों में जो आर्थिक सूचक आकड़ें मिले हैं वे और निराश करने वाले हैं। इस समय अमरीकी विकास दर महज 1.8 फीसदी है। गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट का आकलन है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। बेरोजगारी की रिपोर्ट और स्याह तस्वीर पेश कर रही है। इस समय अमरीकी में बेरोजगारी वृद्धि दर लगभग 9 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

■ विक्रम उपाध्याय

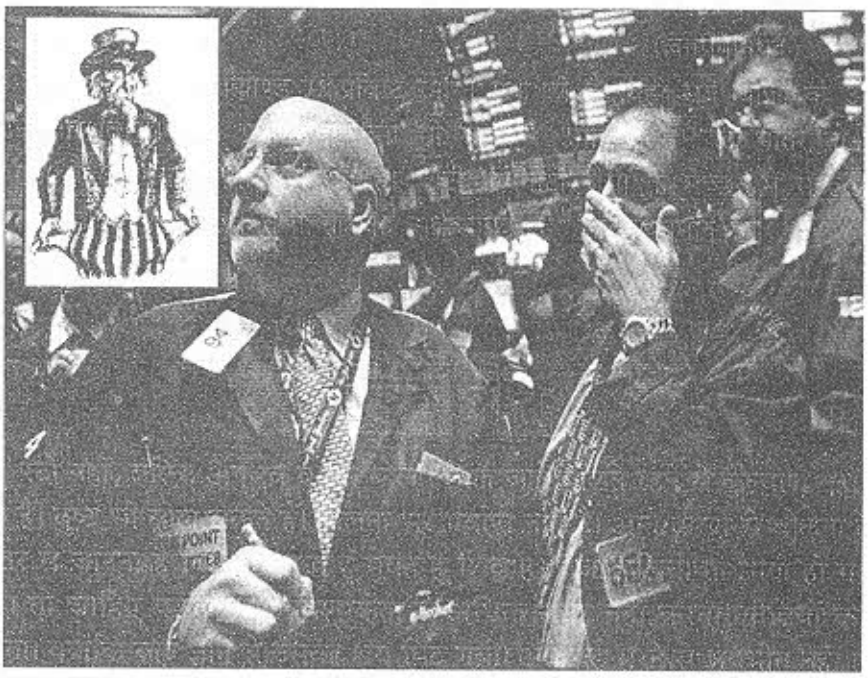

कर्ज की अर्थव्यवस्था अमरीका के लिए फांस बनती जा रही है। वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि अमरीकी लोगों को तनख्वाह के लाले पड़ जाएंगे। आशंका यह भी है कि अगस्त के बाद अमरीका अपने नागरिकों दिए जा रहे सामाजिक सुरक्षा भत्ते को रोक सकता है। इस समय अमरीकी सरकार 14.3 खरब डॉलर तक ऋण ले सकती है। यानि इतनी रकम तक के बांड जारी कर सकती है। यदि उससे अधिक ऋण की जरूरत पड़ी तो इसके लिए अमरीकी संसद से मंजूरी लेनी आवश्यक है। 1966 से लेकर अभी तक अमरीकी संसद 40 बार से अधिक ऋण की सीमा बढ़ा चुका है और 2001 से अभी तक दस बार।

वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि अमरीकी लोगों को तनख्वाह के लाले पड़ जाएंगे।

स्पष्ट है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। एक और आर्थिक सुनामी का डर सिर्फ ओबामा प्रशासन को ही नहीं है, बल्कि अब विश्व बैंक भी मिन्नते कर रहा है कि अमरीकी कांग्रेस को ऋण लेने की सीमा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

खतरा यह भी है कि ओबामा अपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण अमरीकी

डॉलर पर बुरा असर पड़ेगा। अमरीकी अर्थशास्त्री इस बात के लिए भयभीत हो रहे हैं कि कहीं इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होने की पहचान न खत्म हो जाए उसकी जगह चीन की मुद्रा युआन न ले ले। अमरीका की अर्थव्यवस्था अपने ही कर्ज के बोझ से डूब रही है।

हाल के दिनों में जो आर्थिक सूचक आकड़ें मिले हैं वे और निराश करने वाले हैं। इस समय अमरीकी विकास दर महज 1.8 फीसदी है। गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट का आकलन है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। बेरोजगारी की रिपोर्ट और स्याह तस्वीर पेश कर रही है। इस समय अमरीकी में बेरोजगारी वृद्धि दर लगभग 9 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है मांग में कमी आना। लोग अभी भी आवास ऋण और केडिट कार्ड कर्ज के बोझ तले फंसे हुए हैं। हालांकि ओबामा प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि लोगों को आवास ऋण से राहत दिला कर फिर से रियलिटी उद्योग में मांग बढ़ाई जाए। क्योंकि आवास उद्योग के उछाल से अमरीकी बेरोजगारी में कमी आएगी। लेकिन परिणाम उलटा ही मिला। अमीरों ने आवास ऋण पर देय ब्याज में राहत से जो फायदा मिला उसका उन्होंने अपने घरेलू सामानों की खरीद में उपयोग कर लिया। अमरीकी अभी भी मकान खरीदने से कतरा रहे हैं। अमरीकी अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में कमी इस बात से पता से चलती है कि वहां के दस साल की अवधि वाले बांड पर रिटर्न बमुश्किल तीन फीसदी है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था का आधार ही वहां के उपभोक्ता हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का 70 फीसदी भार उपभोक्ता बाजार पर है। जहां से मांग काफी कम निकल रही है। लगातार नौकरियां छिनने, केडिट कार्ड के डिफाल्टर होने और आगे और बड़ी समस्या के आकलन से भयभीत अमरीकी नागरिक खर्चे में कटौती कर रहा है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था का आधार ही वहां के उपभोक्ता हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का 70 फीसदी भार उपभोक्ता बाजार पर है। जहां से मांग काफी कम निकल रही है। लगातार नौकरियां छिनने, केडिट कार्ड